# JNPA and IFC Partner for 1st Blue Financing in India's Maritime Sector

## *The US$ 70 million investment—aligned with Government of India's maritime vision—to boost shore power supply infrastructure*

**Mumbai, September 28th,2026:**

In a landmark move for sustainable maritime development, the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), India's largest container port, has partnered with the International Finance Corporation (IFC) to pioneer the country's first-ever Blue Finance framework for the maritime sector. This strategic collaboration with a member of the World Bank Group focused on the private sector aims to raise targeted capital dedicated exclusively to building eco-friendly, resilient port infrastructure and advancing India's blue economy.

IFC's US$70 million investment will finance Shore Power Supply (SPS) infrastructure across JNPA's terminals and enable ships at berth to switch off diesel engines and connect to land-based electricity—cutting carbon emissions by 63%, reducing harmful air pollution by up to 90%, and creating over 400 jobs. The collaboration aims to elevate India's maritime sector by setting new benchmarks for its ports and elevating them to meet global standards.

As the **first labeled 'blue financing' for port infrastructure in Asia-Pacific**, this project is among the first to be aligned with the new Blue Finance guidelines of the **Indian Ports Act, 2025**. The transaction also represents a historic milestone as the **first DFI investment** in India's state-owned major port authorities.

Shore power technology is new to Indian ports. No major Indian port has yet deployed it at scale commercially. IFC's long-term financing is expected to support the adoption of this emerging technology and demonstrate a replicable financing model that could facilitate similar investments across other Indian ports.

Expressing his views on the collaboration, **Shri Gaurav Dayal, IAS, Chairperson, JNPA,** said, *"Indian ports have not yet commercialized SPS at scale. Funding from international development institutions like IFC will enable JNPA to manage early-stage commercial risks, build operational experience, and bring international best-practices, prior to scale-up. A successful operational and commercial demonstration by India's largest container port would provide proof*

*of concept for broader adoption of SPS across Indian ports and other emerging markets, delivering economic as well as environmental benefits. The Project is expected to demonstrate JNPA's pioneering commitment to achieving Harit Sagar Green Port Guidelines, setting a new benchmark for Indian Ports infrastructure sector."*

Speaking on the partnership, **Manuel Reyes Retana, Division Director, South Asia, IFC** said, *"India's ports are critical to its trade, and this investment is about making them future-ready. By partnering with India's largest and busiest container port we are going beyond an infrastructure upgrade to demonstrate that sustainable financing can work for the country's maritime sector at scale. This is how the World Bank Group adds value: unlocking, mobilizing and expanding access to finance, creating jobs, and helping India scale modern smart infrastructure that expands trade, applies first-in-market innovation, and builds a maritime economy the world will look to."*

India has set itself an ambitious target. The Maritime India Vision 2030, launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, calls for Indian ports to become globally competitive, digitally advanced, and environmentally sustainable by the end of this decade. At the heart of this vision is the Harit Sagar Green Port Guidelines: India's national framework for decarbonizing port operations, reducing pollution, and transitioning the maritime sector to cleaner fuels and technologies. Shore power is one of Harit Sagar's flagship interventions. IFC also supported the development of JNPA's Sustainable Finance Framework to mobilize additional green and blue financing for future investments. DNV's Second Party Opinion confirms that JNPA's framework is in full alignment with the LMA Green Loan Principles and IFC Blue Finance Guidelines.

JNPA remains committed to embedding sustainability across its operations, balancing efficient trade facilitation with long-term environmental responsibility.

*****

**About Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA):**

The Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) is one of India's premier container-handling ports and a key gateway for the country's EXIM trade.
JNPA currently operates five container terminals — NSFT, NSICT, NSIGT, BMCT and APMT. The port also has a shallow water berth for general cargo, operated by NSDT. Its liquid cargo facilities include a terminal managed by the BPCL-IOCL consortium and an

additional liquid cargo terminal developed by JNPA and operated by M/s JSW-JNPT Liquid Terminal Pvt. Ltd. The port's coastal berth further strengthens maritime connectivity with other Indian ports and supports the growth of coastal cargo and container movement.

Spread across 277 hectares, JNPA also operates a strategically located multi-product Special Economic Zone (SEZ) equipped with modern infrastructure and facilities to support export-oriented industries and promote trade and investment.

Looking ahead, JNPA is developing the Vadhvan Port, an all-weather, deep-draft, greenfield port in Maharashtra and the 13th Major Port of India.

**For media enquiries, please contact:**
Ambika Singh |Sr. Manager (Marketing), JNPA
+91 9920372677 | ambikasingh@jnport.gov.in

---

JN Port: www.jnport.gov.in |LinkedIn: JNPA- Jawaharlal Nehru Port Authority
X: @JNPort |Instagram: @jnpaport |Facebook: @JNPA

# जेएनपीए और आईएफसी की साझेदारी; भारत के समुद्री क्षेत्र में पहली 'ब्लू फाइनेंसिंग' पहल

*भारत सरकार की समुद्री क्षेत्र की दूरदर्शी योजना के अनुरूप 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश; तटीय विद्युत् आपूर्ति (एसपीएस) बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने की पहल*

**मुंबई, 28 सितंबर 2026:**

संधारणीय समुद्री विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, भारत के सबसे बड़े कंटेनर पत्तन जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से समुद्री क्षेत्र के लिए देश की पहली 'ब्लू फाइनेंस' योजना विकसित करने की पहल की गई है। विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र पर केंद्रित सदस्य संस्था के साथ यह रणनीतिक सहयोग पर्यावरण-अनुकूल और जलवायु- पत्तन अवसंरचना के निर्माण तथा भारत की 'ब्लू इकॉनमी' को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लक्षित पूंजी जुटाने पर केंद्रित है।

आईएफसी के 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश से जेएनपीए के विभिन्न टर्मिनलों में तटीय विद्युत् आपूर्ति (एसपीएस) अवसंरचना विकसित की जाएगी। इसके माध्यम से पत्तन पर खड़े जहाज अपने डीजल इंजन बंद कर सकेंगे और भूमि-आधारित बिजली आपूर्ति से जुड़ सकेंगे। इससे कार्बन उत्सर्जन में 63% तक की कमी, हानिकारक वायु प्रदूषण में 90% तक की कमी आएगी तथा 400 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह साझेदारी भारत के समुद्री क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से पत्तनों के लिए नए मानदंड स्थापित करने तथा उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने पर केंद्रित है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पत्तन अवसंरचना के लिए 'ब्लू फाइनेंसिंग' के रूप में लेबल की गई यह पहली पहल है। यह परियोजना भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के तहत जारी नए 'ब्लू फाइनेंस' दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई शुरुआती परियोजनाओं में शामिल है। यह लेन-देन भारत के राज्य-स्वामित्व वाले प्रमुख पत्तन प्राधिकरणों में किसी विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) द्वारा किए गए पहले निवेश के रूप में भी एक ऐतिहासिक पहल है।

तटीय विद्युत तकनीक भारतीय पत्तनों के लिए एक नई तकनीक है। अभी तक किसी भी प्रमुख भारतीय पत्तन में इसे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक स्तर पर लागू नहीं किया गया है। आईएफसी का दीर्घकालिक वित्तपोषण इस उभरती हुई तकनीक को अपनाने में सहयोग करेगा तथा एक ऐसे पुनरावृत्त योग्य वित्तपोषण मॉडल को प्रदर्शित करेगा, जिससे भारत के अन्य पत्तनों में भी इसी प्रकार के निवेश को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है।

इस सहयोग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए **जेएनपीए के अध्यक्ष, श्री गौरव दयाल, भा. प्र. से.** ने कहा, *"भारतीय पत्तनों में अभी तक बड़े पैमाने पर एसपीएस का व्यावसायिक उपयोग शुरू नहीं हुआ है। आईएफसी जैसी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तपोषण जेएनपीए को परियोजना के शुरुआती चरण में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक जोखिमों का प्रबंधन करने, प्रचालन संबंधी अनुभव विकसित करने तथा बड़े पैमाने पर विस्तार से पहले अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाएगा। भारत के सबसे बड़े कंटेनर पत्तन द्वारा एसपीएस का सफलतापूर्वक प्रचालन एवं व्यावसायिक स्तर पर प्रदर्शन, भारत के अन्य पत्तनों तथा अन्य उभरते बाजारों में एसपीएस के व्यापक स्तर पर अपनाए जाने के लिए इस तकनीक की व्यवहार्यता का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इससे आर्थिक के साथ-साथ पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे। यह परियोजना 'हरित सागर ग्रीन पोर्ट' दिशानिर्देशों को हासिल करने के लिए जेएनपीए की अग्रणी पहल को प्रदर्शित करने के साथ-साथ भारतीय पत्तन अवसंरचना क्षेत्र के लिए एक नया मानदंड स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"*

इस साझेदारी पर बोलते हुए **दक्षिण एशिया, आईएफसी के डिवीजन निदेशक, मैन्युएल रेयेस रेताना** ने कहा, *"भारत के व्यापार में पत्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह निवेश उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार करने की दिशा में है। भारत के सबसे बड़े और व्यस्ततम कंटेनर पत्तन के साथ साझेदारी के माध्यम से हम केवल पत्तन अवसंरचना के उन्नयन तक सीमित नहीं रह रहे हैं, बल्कि यह भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि देश के समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सतत वित्तपोषण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। यही विश्व बैंक समूह के योगदान का प्रमुख स्वरूप है — वित्तपोषण के नए अवसर उपलब्ध कराना, पूंजी जुटाना और वित्त तक पहुंच का विस्तार करना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा भारत में आधुनिक और स्मार्ट अवसंरचना के विस्तार में सहायता करना। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बाजार में पहली बार लागू होने वाले नवाचारों को अपनाने में मदद मिलेगी और ऐसी समुद्री अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहयोग मिलेगा, जिसकी ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित हो।"*

भारत ने सागरी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पत्तन , पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030' के तहत इस दशक के अंत तक भारतीय पत्तनों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, डिजिटल रूप से उन्नत और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस विज़न के केंद्र में 'हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश' हैं, जो पत्तन परिचालन को डीकार्बोनाइज करने, प्रदूषण कम करने तथा समुद्री क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों की ओर ले जाने के लिए भारत की राष्ट्रीय नीति है। तटीय विद्युत 'हरित सागर' के प्रमुख उपायों में से एक है। भविष्य के निवेश के लिए अतिरिक्त ग्रीन और ब्लू फाइनेंसिंग जुटाने के उद्देश्य से आईएफसी ने जेएनपीए के संधारणीय वित्तपोषण ढांचे के विकास में भी सहयोग किया है। डीएनवी की सेकंड पार्टी ओपिनियन ने पुष्टि की है कि जेएनपीए का यह ढांचा एलएमए ग्रीन लोन प्रिंसिपल्स और आईएफसी ब्लू फाइनेंस दिशानिर्देशों के साथ पूर्णतः अनुरूप है।

जेएनपीए अपने सभी प्रचालनों में संधारणीयता को समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और कुशल व्यापार सुविधा के साथ दीर्घकालिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने पर निरंतर जोर देता है।

*****

**जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) के बारे में:**

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जनेप प्राधिकरण) भारत के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पतनौ में से एक है।26 मई 1989 को अपनी स्थापना के बाद से, जनेप प्राधिकरण ने एक बल्क कार्गो टर्मिनल से देश के प्रमुख कंटेनर पत्तन में परिवर्तन किया है।

वर्तमान में, जनेप प्राधिकरण पांच कंटेनर टर्मिनलों एन.एस.एफ.टी, एन.एस.आई.सी.टी, एन.एस.आई.जी.टी, बी.एम.सी.टी और ए.पी.एम.टी का संचालन करता है| पत्तन में सामान्य कार्गो के लिए उथले पानी की बर्थ भी है।इसका संचालन न्हावा शेवा डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसडीटी) द्वारा किया जाता है। जेएनपीए पत्तन परिसर में स्थित एक तरल कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन बीपीसीएल-आईओसीएल कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है, जबकि जेएनपीए द्वारा विकसित अतिरिक्त तरल कार्गो टर्मिनल का प्रचालन मेसर्स जेएसडब्ल्यू-जेएनपीटी लिक्विड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नव-निर्मित तटीय बर्थ देश के अन्य पत्तनों को जोड़ने के साथ-साथ तटीय कंटेनर यातायात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

277 हेक्टेयर भूमि पर बसा जनेप प्राधिकरण भारत में निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया बहु-उत्पाद विआक्षे भी संचालित करता है।

जेएनपीए, महाराष्ट्र में भारत के 13वें महा पत्तन, वाढवण में एक सभी मौसमों में सक्षम, गहरे डुबाव वाला, ग्रीनफील्ड पतन भी विकसित कर रहा है। इसके वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पत्तनो में शामिल होने की संभावना है, यह इसके स्थापना से ही 100% हरित पत्तन होगा।

**अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जाएँ:**

जेएन पोर्ट : www.jnport.gov.in | लिंक्डइन: JNPA- Jawaharlal Nehru Port Authority

एक्स: @JNPort | इंस्टाग्राम: @jnpaport | फेसबुक: @JNPA

**मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:**

अंबिका सिंह | वरिष्ठ प्रबंधक (विपणन), जनेप प्राधिकरण

मोबाइल नंबर: +91 9920372677 | ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

# जेएनपीए आणि आयएफसी यांची भागीदारी; भारताच्या सागरी क्षेत्रातील पहिल्या 'ब्लू फायनान्सिंग' उपक्रमाला सुरुवात

*भारत सरकारच्या सागरी क्षेत्रातील दूरदृष्टीशी सुसंगत यूएस$ 70 दशलक्ष गुंतवणूक; जहाजांसाठी शोर पॉवर सप्लाय पायाभूत सुविधा बळकट करण्यास चालना*

**मुंबई,28 सप्टेंबर 2026:**

शाश्वत सागरी विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने (जेएनपीए), आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळासोबत (आयएफसी) भागीदारी करत देशाच्या सागरी क्षेत्रासाठी प्रथमच 'ब्लू फायनान्स' योजना विकसित करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. जागतिक बँक समूहाच्या खासगी क्षेत्रावर केंद्रित असलेल्या सदस्य संस्थेसोबतची ही धोरणात्मक भागीदारी पर्यावरणपूरक आणि हवामान बदलास सक्षम अशा बंदर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तसेच भारताच्या 'ब्लू इकॉनॉमी'ला चालना देण्यासाठी विशेष उद्देशाने भांडवल उभारण्यावर केंद्रित आहे.

आयएफसीची यूएस$ 70 दशलक्ष गुंतवणूक जेएनपीएच्या विविध टर्मिनल्समध्ये शोर पॉवर सप्लाय (एसपीएस) पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे बंदरात उभी असलेली जहाजे डिझेल इंजिन बंद करून जमिनीवरून उपलब्ध होणाऱ्या वीजपुरवठ्याशी जोडली जाऊ शकतील. यामुळे कार्बन उत्सर्जनात ६३% पर्यंत घट, हानिकारक वायू प्रदूषणात ९०% पर्यंत घट होण्यास मदत होणार असून, ४०० हून अधिक रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या सहकार्याचा उद्देश भारताच्या सागरी क्षेत्राला नवी दिशा देत बंदरांसाठी नवे मानदंड प्रस्थापित करणे आणि त्यांना जागतिक दर्जाच्या मानकांशी सुसंगत बनवणे हा आहे.

आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील बंदर पायाभूत सुविधांसाठी 'ब्लू फायनान्सिंग' म्हणून मान्यता मिळालेला हा पहिला उपक्रम असून, भारतीय बंदर अधिनियम, 2025 अंतर्गत नव्याने लागू करण्यात आलेल्या 'ब्लू फायनान्स' मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असलेल्या सुरुवातीच्या प्रकल्पांपैकी हा एक आहे. ही वित्तीय भागीदारी भारतातील राज्य-स्वामित्वाच्या प्रमुख बंदर प्राधिकरणांमध्ये विकास वित्तीय संस्थेकडून (डीएफआय) करण्यात आलेली पहिली गुंतवणूक म्हणूनही ऐतिहासिक ठरली आहे.

शोर पॉवर तंत्रज्ञान भारतीय बंदरांसाठी अद्याप नव्या टप्प्यात आहे. भारतातील कोणत्याही प्रमुख बंदरात व्यावसायिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात या तंत्रज्ञानाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. आयएफसीचा दीर्घकालीन वित्तपुरवठा या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास सहाय्य करेल, तसेच इतर भारतीय बंदरांमध्येही अशाच प्रकारच्या गुंतवणुकीला चालना देणारे पुनरुत्पादित करता येण्याजोगे वित्तपुरवठा मॉडेल विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.

या सहकार्याबाबत आपले मत व्यक्त करताना **जेएनपीएचे अध्यक्ष श्री. गौरव दयाल, भा. प्र. से.** म्हणाले, *"भारतीय बंदरांमध्ये अद्याप मोठ्या प्रमाणावर एसपीएसचे व्यावसायिकीकरण झालेले नाही. आयएफसीसारख्या आंतरराष्ट्रीय विकास वित्तीय संस्थांकडून मिळणारा वित्तपुरवठा जेएनपीएला या तंत्रज्ञानाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील व्यावसायिक जोखीम व्यवस्थापित करण्यास, कार्यान्वयनाचा अनुभव विकसित करण्यास आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यास सक्षम करेल. भारताच्या सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदराकडून एसपीएसची यशस्वी*

*कार्यान्वयन व व्यावसायिक स्तरावरील प्रात्यक्षिक अंमलबजावणी झाल्यास, भारतातील इतर बंदरांमध्ये तसेच इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये एसपीएसचा व्यापक अवलंब करण्यासाठी ही संकल्पना व्यवहार्य असल्याचे सिद्ध होईल आणि त्यातून आर्थिक तसेच पर्यावरणीय लाभ साध्य होतील. 'हरित सागर' ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करण्यासाठी जेएनपीएची पुढाकार घेणारी भूमिका अधोरेखित करत, हा प्रकल्प भारतीय बंदर पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी नवा मानदंड प्रस्थापित करेल, अशी अपेक्षा आहे."*

या भागीदारीबाबत बोलताना **आयएफसीच्या दक्षिण आशिया विभागाचे विभाग संचालक मॅन्युएल रेयेस रेतान**ा म्हणाले, *"भारताच्या व्यापारासाठी देशातील बंदरे अत्यंत महत्त्वाची आहेत आणि ही गुंतवणूक त्यांना भविष्यातील गरजांसाठी सक्षम करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक व्यस्त कंटेनर बंदरासोबत भागीदारी करताना आम्ही केवळ पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीपुरते मर्यादित न राहता, भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत वित्तपुरवठा प्रभावीपणे कार्य करू शकतो, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जागतिक बँक समूह अशा प्रकारे मूल्यवर्धन करतो – वित्तपुरवठ्याचे नवे मार्ग खुले करणे, भांडवलाची उभारणी व उपलब्धता वाढवणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि व्यापारवृद्धीला सहाय्य करणाऱ्या आधुनिक व स्मार्ट पायाभूत सुविधांचा भारतात विस्तार करण्यास मदत करणे. तसेच, बाजारपेठेत प्रथमच वापरल्या जाणाऱ्या नवोन्मेषांना प्रोत्साहन देत, जागतिक स्तरावर आदर्श ठरेल अशा आधुनिक सागरी अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी भारताला सक्षम करणे, हा या भागीदारीचा महत्त्वाचा उद्देश आहे."*

भारताने सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. बंदर, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 'मेरीटाइम इंडिया व्हिजन २०३०' अंतर्गत या दशकाच्या अखेरीस भारतीय बंदरांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, डिजिटलदृष्ट्या प्रगत आणि पर्यावरणपूरक बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी 'हरित सागर ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वे' असून, बंदरांच्या कार्यप्रणालीतील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे आणि सागरी क्षेत्राला स्वच्छ इंधन व तंत्रज्ञानाकडे वळविण्यासाठी ही भारताची राष्ट्रीय धोरण आहे. शोर पॉवर हा 'हरित सागर' मार्गदर्शक तत्त्वांमधील प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहे. भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त ग्रीन आणि ब्लू फायनान्सिंग उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आयएफसीने जेएनपीएच्या शाश्वत वित्तपुरवठा धोरणच्या विकासालाही सहकार्य केले आहे. डीएनव्हीच्या सेकंड पार्टी ओपिनियननुसार, जेएनपीएचे हे धोरण एलएमए ग्रीन लोन प्रिन्सिपल्स आणि आयएफसीच्या ब्लू फायनान्स मार्गदर्शक तत्त्वांशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.

जेएनपीए आपल्या कार्यप्रणालीच्या प्रत्येक स्तरावर शाश्वततेचा समावेश करण्यासाठी कटिबद्ध असून, कार्यक्षम व्यापार सुलभीकरणासोबत दीर्घकालीन पर्यावरणीय जबाबदारीचा समतोल साधण्यावर भर देत आहे.

*****

**जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) विषयी माहिती:**

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जनेप प्राधिकरण) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांपैकी एक आहे. 26 मे 1989 रोजी स्थापना झाल्यापासून, जनेप प्राधिकरण एक बल्क कार्गो टर्मिनलवरून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरात रूपांतरित झाले आहे.

सध्या, जनेप प्राधिकरण पाच कंटेनर टर्मिनल्स चालवते एन एस एफ टी, एन एस आय सी टी, एन एस आय जी टी, बी एम सी टी आणि ए पी एम टी. न्हावा शेवा डिस्ट्रिब्युशन टर्मिनल प्रा. लि. (एनएसडीटी) द्वारे संचालित सामान्य मालासाठी एक उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. जनेप प्राधिकरण पोर्टवर उपस्थित असलेले लिक्विड कार्गो टर्मिनल बीपीसीएल आयओसीएल कन्सोर्टियम द्वारे व्यवस्थापित केले जाते आणि जेएनपीएने विकसित केलेले अतिरिक्त लिक्विड कार्गो टर्मिनल मेसर्स जेएसडब्ल्यू - जेएनपीटी लिक्विड टर्मिनल प्रा. लि. द्वारे चालवले जाते. या व्यतिरिक्त, नव्याने बांधलेला किनारी धक्का इतर भारतीय बंदरांना जोडतो आणि किनारपट्टीवरील कंटेनरची वाहतूक वाढवते.

277 हेक्टर जमिनीवर वसलेले, जनेप प्राधिकरण भारतातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, काळजी पूर्वक डिझाइन केलेले बहुउत्पादक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) देखील चालवते.

जेएनपीए वाढवण येथे एक सर्व-हवामान, डीप ड्राफ्ट, ग्रीनफिल्ड बंदर विकसित करत आहे, जे महाराष्ट्रातील भारताचे १३वे मोठे बंदर असेल. हे जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट १० बंदरांमध्ये स्थान मिळवणार आहे आणि स्थापनेपासून १००% हरित बंदर असेल.

**मीडिया चौकशीसाठी, कृपया संपर्क साधा:**

अंबिका सिंग | सीनियर मॅनेजर (मार्केटिंग), जनेप प्राधिकरण

मोबाईल क्रमांक: +919920372677 | ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

**अधिक माहितीसाठी आमच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडियाला भेट द्या:**

जेएन पोर्ट : www.jnport.gov.in | लिंक्डइन: JNPA- Jawaharlal Nehru Port Authority

एक्स: @JNPort | इंस्टाग्राम: @jnpaport | फेसबुक: @JNPA